राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, Email- pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक प. 1(124) ग्रावि/अनु–8/नीति आयोग/2017 जयपुर, दिनांक :–

04 SEP 2019

वीडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 22.08.2019 को आशान्वित जिला योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग आयोजित की गयी जिसमें आशान्वित जिलों के कलक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि संबंधित जिले से एवं विभागों के राज्य स्तरीय अधिकारियों, राज्य प्रभारी जयपुर मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग में शामिल हुए।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के प्रारम्भ में राज्य नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा आशान्वित जिला योजनान्तर्गत 49 संकेतकों के संबंध में अवगत कराया गया तथा आशान्वित जिलों द्वारा माह अप्रेल, मई एवं जून 2019 के दौरान अर्जित डेल्टा रैंकिंग के संबंध में भी अवगत कराया। माह जून 2019 की डेल्टा रैंकिंग में धौलपुर एवं करौली जिले पिछड़े हुए हैं, इनकी क्रमशः 91 एवं 88 डेल्टा रैंक रही हैं, जबकि बारां 23 एवं सिरोही 20वें नम्बर पर रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जिलों ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित संकेतकों के अनुसार अपनी प्रगति प्रस्तुत की तथा लक्ष्य अर्जन में आ रही कठिनाईयों के संबंध में भी अवगत कराया गया।

आशान्वित जिला धौलपुर– जिला की रैंकिंग माह अप्रेल 2019 में 104 और जून 2019 में 91 रही, वहीं माह मई 2019 में धौलपुर जिले ने सभी 5 गतिविधियों में देश में द्वितीय रैंक हासिल कर 5.00 करोड़ रूपये का पुरस्कार भी प्राप्त किया है। एक माह के अन्तराल में डेल्टा रैंकिंग की अनियमित गिरावट चिन्तनीय है। इस संबंध में 49 संकेतकों के 81 सूचकांकों की बिन्दुवार समीक्षा करने बाबत निर्देश दिये गये।

आशान्वित जिला करौली– करौली जिले की डेल्टा रैंकिंग माह जून 2019 में 88 रही है। इससे पूर्व माह मई 2019 में 106 एवं माह अप्रेल 2019 में 23 वें स्थान पर रहा है। करौली की रैंकिंग में नियमित गिरावट देखी गयी है। माह मार्च 2018 में जिला 31वें नम्बर पर था, वहीं माह दिसम्बर 2018 में 88 व जून 2019 में भी 88 नम्बर पर ही है। डेल्टा रैंकिंग की गिरावट के संबंध में जिला कलक्टर, धौलपुर के द्वारा अवगत कराया कि जिले में योजना की

गतिविधियों में शामिल विभागों में अधिकतर अधिकारी कर्मचारी के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण प्रगति प्रभावित हो रही है। इस संबंध में स्टेट नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया कि रिक्तियों की समस्या करौली जिले के साथ साथ पूरे राज्य में हैं, जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके द्वारा जो कार्य सम्पादित किया है उसके अनुसार क्या प्रगति रही है एवं क्या और कैसे लक्ष्य हासिल किये जा सकते है यह अवगत कराने के निर्देश दिये।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया की पूरे राज्य में प्रतिनियुक्ति पर लगे चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सा कार्मिकों की प्रतिनियुक्तियां समाप्त की गयी है। 31 अगस्त 2019 तक अधिकतर चिकित्सा कार्मिक अपने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लेंगे।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा गत बैठक दिनांक 20.7.2018 में लिये गये निर्णयों को पुनः दोहराते हुए सभी आशान्वित जिलों के कलक्टर्स को निर्देशित किया कि आशान्वित जिले से यदि किसी अधिकारी/कार्मिक का स्थानान्तरण होता है, तो जब तक नवीन अधिकारी/कार्मिक कार्यग्रहण नहीं कर ले तब तक स्थानान्तरित अधिकारी/कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जाए। सभी विभागीय अधिकारियों को भी इस आशय के निर्देश दिये गये कि आशान्वित जिलों के अधिकारी/कार्मिकों को स्थानान्तरित नहीं किया जाए। यदि स्थानान्तरण करना प्रस्तावित/आवश्यक है तो नये अधिकारी/कार्मिक का पदस्थापन आवश्यक रूप से किया जाए।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि करौली जिले के केन्द्रीय प्रभारी श्री वी.श्रीनिवास, अतिरिक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं जन अभाव अभियोग, राज्य प्रभारी के साथ समन्वय कर सभी 49 संकेतकों की विस्तृत समीक्षा करें तथा डेल्टा रैंकिंग में सुधार करने का प्रयास करें।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचायतीराज द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाओं की प्रगति में भी करौली जिला नियमित रूप से पिछड़े रहने के संबंध में भी अवगत कराया। प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण, महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण विकास की योजनाऐं यथा– डांग, सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, पंचायतीराज की 14वां/राज्य वित्त आयोग जैसी योजना की प्रगति पर निरन्तर ध्यान केन्द्रित करने की भी आवश्यकता है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की योजनाओं में प्रगति कम रहने एवं आशान्वित जिला योजना में डेल्टा रैंकिंग में पिछड़ने को गंभीरता से लेते हुए

नीति आयोग द्वारा निर्धारित 49 संकेतकों की साप्ताहिक समीक्षा करने, पोर्टल पर सही एवं समय पर डाटा फीडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

आशान्वित जिला सिरोही– जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा आशान्वित जिला योजना के अन्तर्गत 49 संकेतकों के संबंध में अपना प्रस्तुतीकरण दिया साथ ही अवगत कराया कि जिले में मुख्य विभागों के 50 प्रतिशत पद रिक्त हैं, जिसमें आईसीडीएस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, राजस्व, पंचायतीराज एवं आयोजना शामिल हैं। विभागों में संसाधनों के अभाव के कारण रिपोर्टिंग करने में कठिनाईयां उत्पन्न होती हैं। आईसीडीएस में वजन एवं उंचाई मापन के यंत्र नहीं हैं। कृषि विभाग में मिट्टी परीक्षण की लैब नहीं है। कुपोषित बच्चों के ईलाज के लिए एक सेंटर पिण्डवाडा व आबूरोड़ में खोलने की आवश्यकता बताई। शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा सभी जिलों में कुपोषित बच्चों के ईलाज हेतु सेंटर खोलने की अनुमति प्राप्त नहीं हैं। राज्य में अभी ऐसे 10 जिलों में यह सेंटर संचालित हैं, जिसमें आशान्वित जिलों में से बारां जिला ही शामिल है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत सरकार से शेष चार जिलों में भी उक्त सेंटर प्राथमिकता से खोलने हेतु प्रयास किये जायें।

कौशल विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण पार्टनर की आवश्यकता भी बतायी गई। इस संबंध में शासन सचिव, श्रम विभाग द्वारा अवगत कराया कि मार्च 2019 से नीति आयोग द्वारा कौशल विकास योजनाओं के संबंध में प्रोफार्मा परिवर्तित कर दिया गया है, जिसके कारण भारत सरकार द्वारा संचालित 2 योजनाओं से संबंधित डेटा अब राज्य स्तर से फीड नहीं किया जाता है। नीति आयोग द्वारा राज्यों को केवल राज्य सरकार के स्तर से चलाई जाने वाली योजनाओं के संबंध में ही डेटा फीड करने के निर्देश दिये गये हैं। वर्ष 2019–20 हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित ELSTP तथा RSTP योजनाओं के आवंटन अभी तक नहीं किये गये है केवल वर्ष 2018–19 से लम्बित कोर्सेज ही जारी है। 10 सितम्बर 2019 तक वर्ष 2019–20 के आदेश जारी करने की संभावना बतायी।

आशान्वित जिला जैसलमेर– जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा अपने जिले की प्रगति प्रस्तुत की। मार्च 2018 में निर्धारित बैंच मार्क अनुसार लक्ष्य अर्जन के संबंध में 49 संकेतकों के अनुसार नियमित समीक्षा करने के संबंध में अवगत कराया। जिले द्वारा माह जनवरी, फरवरी 2019 के दौरान वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास में प्रथम स्थान रहने के संबंध में अवगत कराया। इस हेतु जिले को 3 करोड़ राशि का पुरस्कार प्राप्त हुआ है जिसकी केन्द्र एवं राज्य प्रभारियों के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। स्वच्छ पेयजल, 16 हजार परिवारों के घरों में विद्युत कनेक्शन का अभाव, प्रशिक्षण हेतु सहयोगी संस्था कठिन भौगोलिक परिस्थितियॉ तथा मुख्य विभागों के अधिकतर पद रिक्त होने के कारण लक्ष्य अर्जन में आ रही कठिनाईयों के संबंध में भी अवगत कराया।

आशान्वित जिला बारां– अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां द्वारा अपने जिले की प्रगति प्रस्तुत की माह जून 2019 में जिले की रेंक 23वीं रही है। नीति आयोग द्वारा निर्धारित 40 संकेतकों के अनुसार नियमित समीक्षा की जा रही है। माह मई 2019 में जिले की रेंक 5वीं होने के संबंध में अवगत कराया।

खाद्य विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिग के दौरान अवगत कराया कि आशान्वित जिलों में विधिक माप विज्ञान विभाग की प्रयोगशाला हेतु 340 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया जाना है। केन्द्र सरकार द्वारा भूमि आवंटन के पश्चात प्राथमिकता से 50.00 लाख रूपये प्रयोगशाला हेतु आवंटित किये जा सकेगें। जैसलमेर, धौलपुर व बारां में रीको क्षेत्र में एवं सिरोही में जिला उद्योग केन्द्र के समीप भूमि चिन्हित की गयी है। करौली जिले में नगर परिषद द्वारा भूमि चिन्हित की है। इस संबंध में सभी जिला कलक्टर्स को भूमि आवंटन की कार्यवाही तत्परता से करने के निर्देश दिये गये।

अंत में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 20.07.2018 को आयोजित बैठक के दौरान लिये गये निर्णय जिसमें आशान्वित जिले में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक का स्थानान्तरण अन्यत्र होता है, तो नवीन अधिकारी/कार्मिक कार्य ग्रहण नहीं करने तक जिले से कार्यमुक्त की कार्यवाही नहीं की जाए। इन निर्देशों की कड़ाई सें पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इस आशय के निर्णय की माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी अनुमति प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। सभी आशान्वित जिलों के जिला कलक्टर अपने–अपने राज्य प्रभारी एवं केन्द्र प्रभारियों के साथ समन्वय कर नीति आयोग के निर्धारित 49 संकेतकों की समीक्षा करें। निर्धारित लक्ष्य अर्जित करने हेतु कार्य योजना तैयार करें। नीति आयोग द्वारा निर्धारित 49 संकेतकों के अनुसार निर्धारित बैंच मार्क अनुरूप लक्ष्य अर्जन की जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिये। संबंधित विभाग राज्य स्तर से आशान्वित जिलों में निर्धारित सकेतकों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें तथा आशान्वित जिलों के रिक्त पदों पर प्राथमिकता से पदस्थापन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अन्त में वीडियों कांन्फ्रेन्सिंग सधन्यवाद समाप्त हुई।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं
स्टेट नोडल अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं हार्टिकल्चर विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
12. निजी सचिव, निदेशक, एच.सी.एम.रीपा (राज्य प्रभारी अधिकारी करौली)।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।
17. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग (राज्य प्रभारी अधिकारी जैसलमेर)।
18. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
19. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (राज्य प्रभारी अधिकारी धौलपुर)।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं राज्य प्रभारी अधिकारी सिरोही।
21. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य प्रभारी अधिकारी बारां)।
22. जिला कलेक्टर, (बारां, धौलपुर, सिरोही, करौली, जैसलमेर)।
23. प्रोग्रामर, ग्रा.विकास को अपलोड हेतु।

04/09/19

(हितबल्लभ शर्मा)
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)